परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 19 जून 2013 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	14 जून 13

परियोजना का नाम	कर्नाटक एकीकृत और सम्पोषणीय जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	43253-024
स्थिति	प्रस्तावित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	बहुसेक्टर/बहुसेक्टर
विषयगत वर्गीकरण	क्षमता विकास पर्यावरण–सम्पोषणीयता अभिशासन निजी क्षेत्र विकास जलवायु परिवर्तन
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	प्रभावी ढंग से लिंग मुख्यधारा में जोड़ना

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/ रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	150,000
योग			यूएस **$ 150,000**

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

–

अस्वैच्छिक पुनर्वास

–

स्वदेशी लोग

–

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

–

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

–

■ विवरण

–

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

कर्नाटक शहरी जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (कार्यक्रम) का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन में एक लोकोपकारी तथा सम्पोषणीय विधि में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी जल आपूर्ति और सफाई (यूडब्ल्यूएसएस) के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए और संबद्ध संस्थाओं को जल उपयोग में दक्षता, उत्पादकता तथा सम्पोषणीयता हेतु सुदृढ़ीकरण के लिए निवेश सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नवोन्मेषी उपायों जैसेकि सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) की संभावनाओं पर भी विचार और कार्यान्वयन किया जाएगा। यह कार्यक्रम एडीबी के "हरितकरण" ("ग्रीनिंग") तथा समावेशिता कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सहायताप्रद होगा, क्योंकि इसका लक्ष्य जल संसाधन अपघटन के बढ़ते प्रभाव वाले अधिक नाजुक पर्यावरणों की सहायता करना है, जो कर्नाटक के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्रायः देखे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम जलवायु–अनुकूल विकास, क्षमता विकास तथा अपनाए जाने हेतु अनुकूल नीति क्रियान्वयन के प्रोत्साहन द्वारा एडीबी की जलवायु परिवर्तन

रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए भी सहायताप्रद होगा। यह बहुदीर्घीकृत दृष्टिकोण की प्रगति में सहायक होगा, जिसमें शामिल हैं : (i) निम्नलिखित के माध्यम से सुधारीकृत योजना और निगरानी : (क) नगर–स्तरीय जल सेक्टर प्रधान–योजना, (ख) सुधारीकृत जल/निकास निगरानी (मात्रा और गुणवत्ता), (ग) एकीकृत जल/अवजल उपचार और पूर्ण सेवा व्याप्ति, तथा (घ) जल लेखांकन तथा जल संरक्षण प्रणाली का प्रोत्साहन। (ii) निम्नलिखित के माध्यम से अधिक कुशल जल अवसंरचना : (क) गैर–राजस्व जल अवमंदन तथा उपयुक्त सेवा प्रदायगी मानक, तथा (ख) एकीकृत शहरी–शहरी तथा शहरी–ग्रामीण थोक जल आपूर्ति प्रणालियों का परीक्षण, जहां उपयुक्त है। (iii) निम्नलिखित हेतु सुधारीकृत अपवहन अवसंरचना तथा सेवाएं : (क) वितरण नेटवर्क तथा उपचार क्षमता की बहाली तथा/अथवा विस्तार, अशोधित अवजल निस्सरण की रोकथाम और अनुप्रवाह गुणवत्ता (नदी) का सुधार; और (ख) अपशिष्ट जल उपचारित निस्सारी का उद्योग/सिंचाई/भूजल पुनर्नवीकरण प्रयोजनों हेतु पुनरूपयोग। (iv) निम्नलिखित के माध्यम से संवर्द्धित संस्थानिक निष्पादन : (क) निजी क्षेत्र सहभागिता, विशेषकर निष्पादन–आधारित प्रबंधन संविदाओं के माध्यम से; (ख) क्षेत्रीय जल प्रचालक एसपीवी'ज की अगुवाई; (ग) सुधारीकृत मांग प्रबंधन तथा शुल्क दर निर्धारण; तथा (घ) नियामक तंत्र का स्थापन। कर्नाटक (राज्य) भारत में सर्वाधिक जल–विपत्तिग्रस्त राज्यों में एक है। मुद्दों में भूतल जल अति दोहनः औद्योगिक और अशोधित अवजल निस्सरण और घटिया जलसंभर प्रबंधन के परिणामस्वरूप नदी जल गुणवत्ता का गिरता स्तर शामिल है। 40 प्रतिशत जिलों में भूजल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। तदापि राज्य के वार्षिक जल उपयोग में 2025 तक 40 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जो सम्पोषणीय आर्थिक विकास तथा गरीबी उपशमन के लिए एक आशंका पैदा करती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जिससे सूखा और बाढ़ की स्थिति और उग्र होने का पूर्वानुमान है, के कारण जल उपलब्धता में और कमी आ सकती है। राज्य की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए कारगर और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन तथा नियंत्रण महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के 2020 हेतु आर्थिक विकास कार्यक्रम में राज्य के पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों (जल सहित) की सम्पोषणीयता को प्राथमिकता दी गई है तथा शहरीकरण और उद्योगीकरण में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के जल और गरीबी उपशमन कार्य सूचियों में निरापद पेय जल तथा सफाई को उच्च प्राथमिकता दी गई है। लगभग 84 प्रतिशत आबादी को पेय जल तथा 38 प्रतिशत को सफाई सुविधा उपलब्ध है। तथापि, बहुत सी मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकी है : केवल 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी'ज) प्रति व्यक्ति मांग की पूर्ति कर सकते हैं, जबकि केवल 11 प्रतिशत में कार्यशील सीवर प्रणाली मौजूद है। अधिकांश यूएलबी'ज वितरण प्रणालियां अकुशल हैं तथा जल स्तरों हेतु अलेखाकृत की संख्या ऊंची है (30–70 प्रतिशत)। तेजी से बढ़ रही शहरी तथा औद्योगिक मांग की पूर्ति, जलाशयों का संरक्षण तथा कारगर उपचार, निस्सारण और निस्सारी अवशेषों का पुनः उपयोग गंभीर चुनौती है। राज्य ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त नीति ढांचा तैयार किया है जिसमें 2002 राज्य जल नीति (समीक्षा अधीन – तथा 2002 शहरी पेय जल आपूर्ति और सफाई नीति शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति 2012, भारत की शहरी सफाई नीति (2010) तथा सेवा स्तर मानदंड (2010) के तहत राष्ट्रव्यापी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह कार्यक्रम (i) सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) तथा (ii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के संभावित दूसरे दौर की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। एडीबी तथा विश्व बैंक की चालू और पूरी की जा चुकी परियोजनाओं से सीखे गए सबकों से (i) कार्यान्वयन के दौरान समुदाय तथा स्थानीय एनजीओ'ज को शामिल करने, (ii) परिवर्तनशील व्यवहारों पर लक्ष्य किए गए जागरूकता अभियानों का संचालन, (iii) स्पष्ट रेखांकित निष्पादन लक्ष्यों के साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता लगातार बढ़ाने, (iv) पूर्ण स्टाफयुक्त परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करने, (v) दीर्घकालीन सम्पोषणीयता के लिए प्रगति सुधार का महत्व समझ में आया है। यह कार्यक्रम उपरोक्त सबकों के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसमें यूएलबी की इसकी संरचना तथा डिजाइन के सुधार की इच्छा शामिल की गई है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बहुट्रांश वित्तीयन सुविधा (एमएफएफ) का उपयोग किया जाएगा। एमएफएफ इस निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि यह निम्न हेतु सबसे कारगर रूपात्मकता हैः (i) स्थानीयकृत भौगोलिक क्षेत्रों में परियोजना परिणाम अधिकतम करने तथा उनके मापन हेतु; (ii) क्षेत्रीय उपयोगिताओं के साथ अतिरिक्त नगरपालिकाओं के जुड़ने पर स्तर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबद्ध दक्षताएं उपलब्ध कराने हेतु; तथा; (iii) क्षमता विकास के मिश्रण, नीति क्रियान्वयन तथा अवसंरचना प्रावधान हेतु सहायता के लिए। एमएफएफ क्लाइंट को एक सुसंरचित मार्ग मानचित्र कार्यक्रम के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु सक्षम बनाएगा, जो सुस्पष्ट परिभाषित मानदंडों तथा मांग एवं यूएलबी की प्रगति सुधारों हेतु इच्छा के महत्व को प्रकट करने वाली प्रक्रिया के संयोजन से तैयार किया गया है। यह रूपात्मकता निम्न की दृष्टि से पूर्ण उपयुक्त है (i) इस सेक्टर में राज्य का बढ़िया रिकॉर्ड ओर सुधारों हेतु प्रबल इच्छा तथा (ii) निष्पादक अभिकरण (ईए'ज) की प्रामाणिक क्षमता। अनुपूरक परिशिष्ट "क" में इस एमएफएफ के घटक रेखांकित किए गए हैं तथा यह स्पष्ट करने हेतु एक तर्काधार उपलब्ध कराया गया है कि एमएफएफ इस कार्यक्रम के लिए अन्य साधनों तथा रूपात्मकताओं की अपेक्षा अधिक उपयुक्त क्यों है।

■ विकास प्रभाव

कर्नाटक में चुनिंदा नदी उपघाटियों में सम्पोषणीय जल आपूर्ति सुरक्षा

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
परिणाम की दिशा में प्रगति	–

आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
विकास उद्देश्यों की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
विकास परियोजनाओं की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
महत्वपूर्ण परिवर्तन	–

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	–
परामर्शी सेवाएं	
–	
अधिप्राप्ति	
–	
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	
http://www.adb.org/projects/43253-024/business-opportunities	

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	28 जनवरी 13
तथ्य–अन्वेषण	03 अप्रैल 2013 से 11 अप्रैल 2013
प्रबंध समीक्षा बैठक	27 जून 13
अनुमोदन	–
अंतिम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस **$** हजार)	अन्य (यूएस **$** हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
संचयी संवितरण				

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तालय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण	–	–	–	–	–	–	–

संविदाएं और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	तातियाना गैलेगो–लिजोन (Tatiana Gallego-Lizon) (tgallegolizon@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास और जल प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास और वित्त निगम

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/43253-024/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/43253-024/documents